राजस्थान समसामयिकी अगस्त, 2026

संजीव Telegram, App एवं वेबसाइट से निःशुल्क डाउनलोड करें
राजस्थान की आर्थिक समीक्षा एवं बजट का सार संग्रह;
राजस्थान, राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय समसामयिकी (प्रत्येक माह)
साथ ही संजीव App एवं वेबसाइट से आप
Books एवं E-Books भी खरीद सकते हैं।
visit us at : www.sanjivprakashan.com

राजस्थान समसामयिकी अगस्त, 2026
(Current News from Daily Newspapers)

Newspaper of 1 August, 2026

■ **अंगदान जागरूकता में राजस्थान अव्वल–**

नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ने राजस्थान को स्टेट अवॉर्ड फॉर एक्सीलेंस इन ऑर्गन डिजेशन अवेयरनेस के लिए चयनित किया है। 16वें इंडियन ऑर्गन डे 3, अगस्त, 2026 के अवसर पर नई दिल्ली में यह सम्मान दिया गया।

■ **जयपुर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का हाईटेक मॉडल–**

केन्द्र सरकार के सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन (सीआइटीआइआइएस) मिशन के तहत जयपुर में ठोस कचरा प्रबंधन (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट) को पूरी तरह हाईटेक और वैज्ञानिक रूप देने की तैयारी शुरू हो गई है। योजना के तहत जयपुर को 125 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर की गई है। इस बजट से केवल कचरा उठाना ही नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक के जरिये वैज्ञानिक निस्तारण, ग्रीन एनर्जी उत्पादन और पूरे सिस्टम की डिजिटल निगरानी की जाएगी।

जयपुर में ये होगा खास–

♦ **4 आधुनिक ट्रांसफर स्टेशन :** सीतापुरा (250 टीपीडी), मानसरोवर (300 टीपीडी), ब्रह्मपुरी (300 टीपीडी) और कालवाड़ रोड़ (300 टीपीडी) में बनाए जाएँगे।

♦ **एमआरएफ व कॉम्पेक्टर स्टेशन :** 25 टीपीडी क्षमता का मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF) सेंटर और तीन रिफ्यूज कॉम्पेक्टर स्टेशन स्थापित होंगे।

♦ **डिजिटल सिस्टम व सार्वजनिक सफाई :** कचरा संग्रहण और निस्तारण की रियल-टाइम निगरानी के लिए आइसीटी आधारित डिजिटल सिस्टम बनेगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों की सफाई के लिए 20 करोड़ रुपए तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास पर 6.25 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

♦ **जलाशयों के लिए हाई-कैपेसिटी मशीन :** बड़े जलस्रोतों की सफाई के लिए एक विशेष वाटर बॉडी सफेर्स क्लीनिंग मशीन खरीदी जाएगी, जो एक बार में 500 किलोग्राम तक कचरा एकत्र करने में सक्षम होगी।

मिशन के तहत उदयपुर के लिए भी 73.30 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। उदयपुर में 100 टीपीडी क्षमता का नया बायो-सीएनजी प्लांट, 70 टीपीडी का एमआरएफ-कम-आरडीएफ प्लांट स्थापित किया जाएगा।

■ **हाल ही में राज्य सरकार ने स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों के संचालन संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। चिकित्सा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब राज्य में आयोजित सभी स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों में राजकीय ब्लड सेंटर 50 प्रतिशत रक्त का संग्रह करेंगे। इससे पहले यह व्यवस्था 20 प्रतिशत तक सीमित थी।**

■ **1 मेगावाट सोलर प्लांट के लिए अब अधिकतम 2 हैक्टेयर जमीन मिलेगी, 10 प्रतिशत हिस्से पर पेड़ लगाना अनिवार्य होगा–**

एक मेगावाट का सोलर या विंड पावर प्लांट लगाने के लिए अधिकतम 2 हेक्टेयर जमीन ही मिलेगी। सोलर व विंड प्लांट के संयुक्त प्रोजेक्ट के लिए यह 2.5 हेक्टेयर होगी। अब सरकार से मिलने वाली जमीन के 10% हिस्से में पेड़ लगाना अनिवार्य होगा। सोलर व विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाने वाली कंपनियों के लिए जमीन आवंटन के नियम बदल दिए हैं। ऊर्जा विभाग ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है।

अब 1000 मेगावाट से बड़ी परियोजनाओं को भी जमीन–
सरकार ने 1000 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली सौर, पवन, हरित हाइड्रोजन और बिजली भंडारण परियोजनाओं के लिए जमीन देने का रास्ता साफ कर दिया है। अब सुरक्षा राशि सरकार स्थायी नहीं रखेगी। बिजली उत्पादन पर जितनी क्षमता चालू होगी, उसके अनुपात में राशि वापस होगी। 1000 मेगावाट के लिए 10 करोड़ सुरक्षा राशि है। 500 मेगावाट उत्पादन पर 5 करोड़ वापस होंगे।

Newspaper of 2 August, 2026

■ **रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र की नई पहल; देशभर के 455 जिलों में 'मॉडल सौर ग्राम' विकसित किए जा रहे; राजस्थान के हर जिले में 'सूरज वाला गाँव', 41 गाँव मॉडल सौर ग्राम होंगे–**

केन्द्र सरकार की योजना के तहत देशभर में 455 जिलों में

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

'मॉडल सौर ग्राम' विकसित किए जा रहे हैं। इस पहल में राजस्थान के सभी 41 जिलों से एक-एक गांव का चयन किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य गाँवों में रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देकर बिजली खर्च कम करना, पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता घटाना और स्वच्छ ऊर्जा को ग्रामीण स्तर तक पहुँचाना है। योजना के तहत चयनित प्रत्येक मॉडल सौर ग्राम के समग्र विकास के लिए प्रति गांव एक करोड़ रुपए तक की विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं, ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों को रूफटॉप सोलर अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करने पर प्रति स्थापना 1000 रुपए का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।

मॉडल सौर ग्राम के चयन के लिए सामान्य राज्यों में 5000 या उससे अधिक आबादी वाले राजस्व गांव पात्र होंगे। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और द्वीप समूहों में 2000 से अधिक आबादी वाले गांव पात्र माने जाएंगे।

प्रमुख राज्यों में बनेंगे इतने मॉडल सौर ग्राम–

उत्तर प्रदेश	70	छत्तीसगढ़	32
राजस्थान	41	तेलंगाना	28
मध्य प्रदेश	38	गुजरात	26
तमिलनाडु	36	पंजाब	23

Newspaper of 3 August, 2026

■ 9 से 17 अगस्त तक 'हर घर तिरंगा अभियान'–

स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर राज्य में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत तिरंगा रैली, बाइक और साइकिल रैली, चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम और राष्ट्रभक्ति से जुड़े विभिन्न आयोजन होंगे।

■ पीएम नरेन्द्र मोदी ने 'नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान' का शुभारंभ किया–

अगस्त, 2026 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। राजस्थान में उदयपुर के नगर निगम ऑडिटोरियम से वीसी के जरिए संबोधन को सुना गया।

- ♦ प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया यह नशामुक्ति अभियान युवाओं को अपने अंदर परिवर्तन लाने का प्रभावी माध्यम बनेगा।
- ♦ नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन आगामी 100 सप्ताह तक जनभागीदारी के साथ संचालित किया जाएगा।
- ♦ इस अभियान में माय भारत स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, सामाजिक एवं आध्यात्मिक संगठन सहित अनेक संस्थाएँ सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं।
- ♦ इसमें उत्कृष्ट योगदान देने वाले स्वयंसेवकों और संगठनों को 50वें, 75वें और 100वें सप्ताह के पड़ाव पर सम्मानित किया जाएगा।
- ♦ यह सम्मान युवाओं में सार्वजनिक सेवा, सामाजिक नेतृत्व और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को और मजबूत करेगा।
- ♦ राज्य सरकार युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। उच्च शिक्षण संस्थानों में नशीले पदार्थों की रोकथाम के उद्देश्य से 350 से अधिक महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नई किरण नशा मुक्ति केन्द्र स्थापित किए गए हैं।
- ♦ साथ ही राज सवेरा कार्यक्रम के तहत जिला चिकित्सालयों में नशामुक्ति वार्ड स्थापित किए जा रहे हैं तथा नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोर कार्रवाई की जा रही है।

Newspaper of 5 August, 2026

■ राजस्थान में 2 करोड़ 55 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण स्वीकृत हुआ–

2,18,423 करोड़ रुपये को प्रदेश में ऋण स्वीकृत

2,55,91,381 लाभार्थियों को प्रदेश में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ

23 लाख से अधिक लाभार्थियों को वर्ष 2025-26 में ऋण

1.54 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ

राजस्थान में छोटी विनिर्माण इकाइयों-लघु उद्योगों से लेकर रेहड़ी-पटरी वालों के आर्थिक सशक्तीकरण हेतु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से अब तक 2 करोड़ 55 लाख से अधिक लाभार्थियों को संस्थागत वित्त पोषण प्राप्त हुआ है।

- ♦ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत प्रदेश में 2 करोड़ 55 लाख 91 हजार 381 लाभार्थियों को 2 लाख 18 हजार 423 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है।
- ♦ इसमें 1 करोड़ 54 लाख 15 हजार से अधिक महिलाओं लगभग (60%) को 67 हजार 982 करोड़ रुपये से अधिक का मुद्रा ऋण भी शामिल है।
- ♦ वित्तीय वर्ष 2025-26 में ही 23 लाख 74 हजार से अधिक लाभार्थियों को 31 हजार 460 करोड़ रुपये का ऋण वितरित भी हो चुका है।

SP संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

- जून 2026 तक योजना के तहत देशभर में 59 करोड़ 14 लाख से अधिक लोगों को 41 लाख 71 हजार करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया है।
- गैर-कॉर्पोरेट, लघु उद्यमों को 20 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाने के लिए वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी।
- इस योजना में लाभार्थी वित्तपोषण की जरूरतों के अनुरूप शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस वर्गों के लिए ऋण आवेदन कर सकता है।
- योजना से विनिर्माण इकाइयाँ, दुकानदार, फल-सब्जी विक्रेता, ट्रक-टैक्सी ऑपरेटर, खाद्य-सेवा इकाइयाँ, मशीन ऑपरेटर, छोटे उद्योग, कारीगर, खाद्य प्रसंस्करणकर्त्ता, रेहड़ी वालों को ऋण उपलब्ध करवाकर आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है।

Newspaper of 6 August, 2026

■ 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' में राजस्थान में देश में सबसे अधिक 62 लाख, 58 हजार से अधिक किसानों ने योजना में नामांकन किया; 1 करोड़ हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र को बीमित किया गया–

'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत' राजस्थान में देश में सबसे अधिक लगभग 62 लाख, 58 हजार किसानों को योजना में नामांकित किया गया है।

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2025-26 में राज्य के लगभग 2 करोड़, 82 लाख हेक्टेयर सकल फसली क्षेत्र में 1 करोड़ हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को योजना के तहत बीमित किया गया है, जो देश में सर्वाधिक है।
- राज्य के कुल फसली क्षेत्र में बीमित क्षेत्र 36% है, जो देश के औसत 32% से बेहतर है।
- किसानों को मौसम की अनिश्चितता, अतिवृष्टि, सूखा, ओलावृष्टि सहित विभिन्न प्राकृतिक जोखिमों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मिल रहे बीमा कवरेज से आर्थिक सुरक्षा मिली है।

राज्य में वर्ष 2025-26 तक गत पाँच वर्षों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत कुल 5 करोड़, 21 लाख हेक्टेयर से अधिक का बीमित क्षेत्र दर्ज किया गया तथा किसानों द्वारा 4 हजार 650 करोड़ रुपये से अधिक का प्रीमियम हिस्सा जमा किया गया, जो देशभर में सबसे अधिक है।

इस दौरान राज्य में 18 करोड़ 81 लाख से अधिक आवेदन नामांकित हुए और किसानों को 18 हजार, 189 करोड़ रुपये से अधिक के दावों का भुगतान किया गया।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना–

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं (ओलावृष्टि, सूखा, अकाल), कीटों और बीमारियों के कारण फसल के नुकसान से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।
- इसमें किसानों को लागत प्रभावी प्रीमियम पर फसल बीमा दिया जाता है।
- योजना के तहत किसान, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार मिलकर प्रीमियम का भार वहन करते हैं।
- बीमित फसल को निर्धारित जोखिमों के कारण नुकसान होता है, तो पात्र किसान को बीमा दावे के माध्यम से आर्थिक राहत दी जाती है।

राजस्थान में व्यापक फसल बीमा कवरेज–राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वर्ष 2025-26 में चूरू में 13 लाख 35 हजार हेक्टेयर से अधिक, बाड़मेर में 11 लाख, 48 हजार हेक्टेयर और बीकानेर में 9 लाख, 27 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को बीमित किया गया है।

चूरू में 77 प्रतिशत, बाड़मेर में 69 प्रतिशत और नागौर में 47 प्रतिशत सकल फसली क्षेत्र का बीमा कवरेज हुआ है।

■ देश की सबसे बड़ी 'गोट सीमन लैब' रामसर (अजमेर) में स्थापित होगी–

केन्द्रीय प्रवर्तित योजना-नेशनल लाइव स्टॉक मिशन (एनएलएम) के तहत अजमेर के रामसर स्थित राजकीय पशु प्रजनन फार्म में अत्याधुनिक 'गोट सीमन उत्पादन प्रयोगशाला' की स्थापना की जाएगी।

- यह भारत की सबसे बड़ी लैब होगी, जिसमें सालाना दो लाख डोजेज तैयार की जाएंगी।
- इस आधुनिक प्रयोगशाला की स्थापना के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है।
- इस पर 875 लाख रुपये खर्च होंगे, जिसमें 60% हिस्सेदारी केन्द्र और 40% हिस्सेदारी राजस्थान सरकार की है।
- इस लैब का मुख्य उद्देश्य उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले बकरों के सीमन से कृत्रिम गर्भाधान (एआई) को बढ़ावा देना है।

प्रयोगशाला को विश्वस्तरीय तकनीकी और वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप संचालित करने के लिए राजस्थान सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी की है।

- यह एमओयू उत्तर प्रदेश सरकार के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा के साथ किया गया है।

Newspaper of 7 August, 2026

5वें जल सततता पुरस्कार-2026 में राजस्थान को तीन सम्मान मिले–

6 अगस्त, 2026 को द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI) द्वारा इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित 5वें जल सततता पुरस्कार 2026 में राजस्थान की दो संस्थाओं तथा लापोरिया के लक्ष्मण को सम्मानित किया गया।

- चाकसू, जयपुर स्थित ग्रामोदय सामाजिक संस्थान को 'सभी के लिए जल' श्रेणी का विजेता घोषित किया गया। संस्था पूरे राजस्थान में जल-संचयन एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर कार्य करती है।
- श्री सीमेंट लिमिटेड, ब्यावर को 'अपशिष्ट जल उपचार एवं सुरक्षित पुनः उपयोग' श्रेणी का विजेता पुरस्कार मिला।
- ग्राम विकास नवयुवक मंडल, लापोरिया के लक्ष्मण को समुदाय आधारित जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन में योगदान के लिए 'जल चैंपियन-व्यक्तिगत' सम्मान प्रदान किया गया।
- ये पुरस्कार जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, अपशिष्ट जल पुनः उपयोग, जल-उपयोग दक्षता और समुदाय आधारित जल प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देते हैं।

Newspaper of 8 August, 2026

राजस्थान कैबिनेट ने विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी–

सरकारी कर्मियों को रिटायर होने तक मिलेगा बीमा कवर– सरकार ने सरकारी कर्मचारी बीमा नियम-1998 में संशोधन किया है। इसके अनुसार अब सभी राज्य कर्मचारियों को उनकी वास्तविक रिटायरमेंट की तारीख तक बीमा कवरेज मिलेगा। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार राज्य कर्मचारी जिस वित्तीय वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, उस वर्ष 1 अप्रैल को ही उनकी स्टेट इंश्योरेंस पॉलिसी भुगतान हेतु मैच्योर (परिपक्व) हो जाती है। इससे कर्मचारी रिटायरमेंट की तारीख तक बीमा कवरेज से वंचित रह जाता है।

हर जिले में बनेंगे फूड पार्क– कृषि जिंसों के प्रसंस्करण, व्यवसाय व निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 'फूड पार्क विकास नीति-2026' का अनुमोदन भी किया है। फूड पार्कों के विकास के लिए भूमि का आवंटन होगा। प्रत्येक जिले में क्लस्टर आधार पर फूड पार्क विकसित होंगे।

ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट पॉलिसी– वन क्षेत्र के बाहर हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए इस पॉलिसी के तहत बंजर, परती भूमि एवं रेलवे व सड़कों के आसपास की भूमि तथा सिंचित भूमि क्षेत्रों में ट्री कवर बढ़ाया जाएगा। इस पॉलिसी से कार्बन अवशोषण के साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

नई एग्रो व फूड इंडस्ट्री लगाने पर मिलेगी विशेष छूट– एग्रो व फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2026 से इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा। इसमें फल-सब्जी, मसाला, अनाज, तिलहन, दलहन, औषधीय उत्पाद, लघु वन उपज, शहद, दुग्ध व पशु आहार इकाइयों तथा साइलोज व कोल्ड स्टोरेज जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को शामिल किया गया है।

कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले–

- कर्मचारी यूनियनों का चुनाव अब गुप्त मतदान के जरिए होगा।
- राज्य मजदूरी संहिता-2026 को मंजूरी। कर्मचारियों की सैलरी स्लिप देना भी अनिवार्य होगा।
- 'विकसित भारत-जी राम जी योजना' शुरू करने की मंजूरी। ग्रामीण परिवारों को 125 दिन के रोजगार की गारंटी।
- जैसलमेर में मैसर्स स्टार सीमेंट नॉर्थ ईस्ट लिमिटेड और मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के दो सीमेंट प्लांट लगेंगे। यहाँ 6200 करोड़ का निवेश होगा।
- 922 मेगावाट सौर परियोजनाओं को मंजूरी तथा भूमि आवंटन के प्रस्तावों का अनुमोदन।
- नमक खान विस्थापन के लिए डिस्टर्बेंस चार्जेज में बढ़ोतरी। इसके अलावा 9 से 17 अगस्त तक 'हर घर तिरंगा' अभियान चलाया जाएगा।

कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति का अनुमोदन–

कृषि एवं बागवानी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राजस्थान कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2026 का अनुमोदन किया गया है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देना, उपज के मूल्य संवर्धन द्वारा किसानों की आय में वृद्धि, सप्लाई चेन को सुदृढ़ करना तथा प्रोसेस्ड एग्रो उत्पादों के विपणन की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इसमें कृषि प्रसंस्करण उद्योगों फल-सब्जी, मसाला, अनाज, तिलहन, दलहन, औषधीय उत्पाद, लघु वन उपज, शहद, दुग्ध व पशु आहार इकाइयों तथा साइलोज और कोल्ड स्टोरेज जैसी आधारभूत ढांचा विकास परियोजनाओं को शामिल किया गया है।

राजस्थान में हरित क्षेत्र का होगा विस्तार ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट पॉलिसी को मिली स्वीकृति–

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान से प्रेरणा लेते हुए प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 'मिशन हरियालो राजस्थान' प्रारंभ किया गया है।

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

- इसके तहत पाँच वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से लगभग दो वर्षों में करीब 20 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं।
- इस मानसून सीजन में भी 10 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है।
- वन क्षेत्र के बाहर हरित क्षेत्र को और अधिक विस्तार देने के लिए मंत्रिमण्डल ने राज्य में ट्री आउटसाइट फॉरेस्ट पॉलिसी लागू किए जाने की स्वीकृति दी है।
- इस नीति से राज्य में बंजर, परती भूमि एवं रेलवे, सड़कों के आस-पास की भूमि तथा सिंचित भूमि क्षेत्रों में ट्री कवर बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- इससे जैव-विविधता के संरक्षण और जल-संचयन के साथ ही भू-क्षरण पर भी प्रभावी रोकथाम हो सकेगी। इसमें राजस्थान वन नीति, 2023 के तहत लक्ष्यों की प्राप्ति संभव होगी।
- यह नीति कार्बन अवशोषण, रोजगार सृजन तथा गैर-काष्ठ वन उत्पादों एवं कृषि आधारित वृक्ष उत्पादों से बाजार एवं उद्यमिता के अवसर बढ़ाने में भी सहायक होगी।

Newspaper of 11 August, 2026

VB-G RAM G में श्रमिक नियोजना में राजस्थान प्रथम रहा–

10 अगस्त, 2026 तक विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) |VB-G RAM G| के तहत राजस्थान ने 77,814 कार्यों पर 8.59 लाख श्रमिकों को नियोजित कर श्रमिक नियोजन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह योजना राज्य में 1 जुलाई, 2026 से लागू है।

योजना के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी दी गई है, जो पूर्ववर्ती मनरेगा के 100 दिनों से अधिक है।

राजस्थान के लिए 2026-27 में ₹7581.87 करोड़ केन्द्रीय अंश निर्धारित किया गया है। 40% राज्य का मिलाकर कुल प्रावधान लगभग ₹12636 करोड़ बनता है।

योजना में 318 प्रकार के अनुमत कार्य शामिल हैं तथा प्रशासनिक व्यय की सीमा 6% से बढ़ाकर 9% की गई है।

Newspaper of 13 August, 2026

राजस्थान ने 'मजदूरी संहिता (राजस्थान) नियम, 2026' अधिसूचित किए–

12 अगस्त, 2026 को राजस्थान सरकार के श्रम विभाग ने केन्द्रीय मजदूरी संहिता, 2019 (Code on Wages, 2019) की धारा 67 के तहत 'मजदूरी संहिता (राजस्थान) नियम, 2026' को अंतिम रूप से अधिसूचित किया। ये नियम पूरे राजस्थान में प्रभावी हो गए। इसके तहत सामान्य कार्य अवधि अधिकतम 48 घंटे प्रति सप्ताह होगी। लगातार 5 घंटे काम के बाद कम-से-कम 30 मिनट का विश्राम तथा प्रत्येक सप्ताह एक सवैतनिक अवकाश का प्रावधान है।

- कामगारों को अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल और अतिकुशल चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। न्यूनतम मजदूरी निर्धारण के लिए मानकीकृत उपभोग एवं जीवन-यापन आवश्यकताओं को आधार बनाया जाएगा।
- परिवर्तनीय महँगाई भत्ता श्रम ब्यूरो के मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को संशोधित किया जाएगा।
- वेतन अवधि अधिकतम एक माह होगी तथा किसी वेतन अवधि में कुल कटौतियाँ सामान्यत: मजदूरी के 50% से अधिक नहीं हो सकेंगी।
- नियोक्ताओं को कर्मचारी, उपस्थिति, मजदूरी, ओवरटाइम एवं कटौतियों से संबंधित रजिस्टर रखने और वेतन भुगतान के समय वेतन पर्ची देना अनिवार्य होगा।
- नए नियमों ने न्यूनतम मजदूरी एवं वेतन भुगतान से संबंधित राजस्थान के 7 पुराने नियम-समूहों को एकीकृत ढाँचे से प्रतिस्थापित किया है।

Newspaper of 14 August, 2026

राज्य में 473 घुमंतु परिवारों को पक्के घर मिले–

13 अगस्त, 2026 को विमुक्त, घुमंतु एवं अर्धघुमंतु 473 परिवारों को राज्य सरकार ने पक्के घर दिए। ये आवास जयसिंहपुरा खोर की आवासीय योजना में लाभार्थियों को मिले हैं। राज्य में अन्य शहरों में भी इस योजनान्तर्गत आवास तैयार करवाये जा रहे है।

जयपुर में BRICS वित्त मंत्रियों एवं केन्द्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक-2026 सम्पन्न हुई–

12-13 अगस्त, 2026 को भारत की BRICS अध्यक्षता-2026 के तहत BRICS वित्त मंत्रियों एवं केन्द्रीय बैंक गवर्नरों (FMCBG) की पहली बैठक जयपुर में आयोजित हुई। इस बैठक की सह-अध्यक्षता केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की।

- बैठक में वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, वित्तीय स्थिरता, फिनटेक, सीमा-पार भुगतान, सतत वित्त, क्षमता निर्माण तथा Contingent Reserve Arrangement पर सहयोग बढ़ाने पर विचार हुआ।

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

- NDB पर विशेष सत्र : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 'The Role of the New Development Bank in Mobilising Private Capital in Member Countries' विषय पर मुख्य भाषण दिया, जबकि NDB अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ ने विशेष संबोधन किया।

राजस्थान यूथ कॉन्क्लेव-2026 का जयपुर में आयोजन हुआ–

13 अगस्त, 2026 को राजस्थान यूथ कॉन्क्लेव-2026 का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC), जयपुर में किया गया। कार्यक्रम में केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण तथा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं में कौशल विकास, वित्तीय स्वतंत्रता, स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

इस अवसर पर 'राजस्थान स्टार्टअप क्वेस्ट-2026' और सिंगल हॉलिस्टिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (SHPP) का शुभारंभ किया गया। SHPP राज्य की सरकारी खरीद प्रक्रियाओं को एकीकृत और पारदर्शी डिजिटल मंच पर लाने के लिए विकसित किया गया है।

जोधपुर और उदयपुर में डिजिटल प्लेनेटेरियम का शिलान्यास किया गया, जबकि जयपुर में 7D थिएटर और न्यूक्लियर पावर गैलरी तथा उदयपुर के उप-क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र का लोकार्पण किया गया।

राजस्थान समान सिविल संहिता विधेयक, 2026–

13 अगस्त, 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राजस्थान मंत्रिमण्डल ने राजस्थान समान सिविल संहिता विधेयक, 2026 (Rajasthan Uniform Civil Code Bill, 2026) के प्रारूप को मंजूरी दी। इसे 21 अगस्त, 2026 को राजस्थान विधानसभा में विधेयक संख्या 13/2026 के रूप में प्रस्तुत किया गया।

- विधेयक राज्य में विवाह, विवाह-विच्छेद, उत्तराधिकार, भरण-पोषण और सह-जीवन संबंध (Live- in Relationship) से जुड़े कानूनों को समान, पारदर्शी एवं व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करता है तथा इसे संविधान के अनुच्छेद 44 की भावना के अनुरूप तैयार किया गया है।
- विधेयक लागू होने के बाद संपन्न विवाह का 60 दिनों के भीतर पंजीकरण अनिवार्य होगा। साथ ही बहुविवाह पर प्रतिबंध का प्रावधान है; हालांकि विवाह सप्तपदी, निकाह, आनंद कारज, होली यूनियन जैसी परंपरागत धार्मिक विधियों से किए जा सकेंगे।
- सह-जीवन संबंध शुरू करने और समाप्त करने की सूचना/पंजीकरण निर्धारित प्राधिकारी को देना होगा, ताकि संबंधित पक्षों के अधिकारों को कानूनी संरक्षण दिया जा सके।
- बिना वसीयत मृत्यु की स्थिति में संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए समान कानूनी ढाँचा प्रस्तावित किया गया है; जीवित पति/पत्नी, संतान और माता-पिता को प्राथमिक उत्तराधिकारियों में रखा गया है।
- विधेयक के प्रावधान अनुसूचित जनजातियों तथा संविधान द्वारा संरक्षित उनकी पारंपरिक प्रथाओं पर लागू नहीं होंगे।
- इस विधेयक का प्रारूप उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आधारित है।

Newspaper of 16 August, 2026

स्वतंत्रता दिवस-2026 पर राजस्थान के दो पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक मिला–

14 अगस्त, 2026 को केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस-2026 के अवसर पर राजस्थान पुलिस के एसीपी सुरेंद्र सिंह राणावत तथा एएसपी महेन्द्र कुमार भगत को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान करने की घोषणा की।

राजस्थान पुलिस को कुल 16 सेवा पदक मिले जिसमें 2 राष्ट्रपति पदक (PSM) तथा 14 सराहनीय सेवा पदक मिले।

राजस्थान का 80वाँ राज्य-स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह बीकानेर में मनाया गया–

80वाँ राज्य-स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त, 2026 को डॉ. करणी सिंह स्टेडियम, बीकानेर में आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। बीकानेर ने 18 वर्ष बाद इस राज्य-स्तरीय समारोह की मेजबानी की।

'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली बार राज्य-स्तरीय समारोह में इसका सामूहिक गायन हुआ।

Newspaper of 17 August, 2026

राजस्थान सरकार ने आशा सहयोगिनियो का मानदेय 10 फीसदी बढ़ाया–

हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज्य में कार्यरत आशा सहयोगिनियों का मानदेय 10 प्रतिशत बढ़ाया है। वर्तमान में आशा सहयोगिनियों को प्रतिमाह पाँच हजार रुपए मानदेय मिल रहा है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं, सहायिकाओं और साथिनों को प्रति खाते 1100 रुपए राशि रक्षाबंधन गिफ्ट के तौर पर डीबीटी से दिए गए।

मथुरा से नागदा (567.86 किमी.) तक राजस्थान के भरतपुर, कोटा होकर जाने वाला दिल्ली-मुम्बई 2 लेन रेलवे ट्रेक 4 लेन का होगा; एक साथ चार ट्रेने चलेंगी–

राजस्थान से गुजरने वाला व्यस्ततम दिल्ली-मुंबई 2 लेन रेलवे ट्रेक पर दबाव कम करने के लिए मथुरा से नागदा के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाई जाएगी। यह परियोजना उत्तरप्रदेश, राजस्थान और मध्यप्रदेश को जोड़ेगी।

उल्लेखनीय है कि यह परियोजना स्वीकृति की तिथि से पाँच वर्ष में पूरी की जाएगी। नई लाइन पर ट्रैनों की अधिकतम गति 160 किमी. प्रति घंटा रखी गयी है, जिससे ट्रेनों के परिचालन में तेजी आएगी।

- **मुख्यमंत्री ने किशोरी बालिका योजना का शुभारंभ किया–** अगस्त, 2026 में मुख्यमंत्री ने राज्य के 27 आकांक्षी ब्लॉक्स में किशोरी बालिका योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत पाँच लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक सौंपे।

साथ ही, कैश प्लस मॉडल व्यवहार परिवर्तन रणनीति से संबंधित पुस्तक, मातृ और शिशु पोषण पर आधारित सफलता की कहानियों की संग्रह पुस्तिका, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं के लिए बच्चों के विकास में देरी और दिव्यांग बच्चों में संकेतकों की पहचान से जुड़ी मार्गदर्शिका और नवचेतना हैण्डबुक का विमोचन किया।

- **योगाचार्य ढाकाराम को वियतनाम में दो अन्तरराष्ट्रीय सम्मान मिले–**

16 अगस्त, 2026 को जयपुर के प्रसिद्ध योग शिक्षक योगाचार्य ढाकाराम को हनोई (वियमनाम) में आयोजित 5वें अन्तरराष्ट्रीय योग एवं समग्र स्वास्थ्य सम्मेलन में 'इंटरनेशनल योगश्री अवॉर्ड 2026' से सम्मानित किया गया। उन्हें अगस्त 2026 में प्रतिष्ठित 'हो ची मिन्ह अवॉर्ड' भी प्रदान किया गया।

सम्मान का आधार–उन्हें योग शिक्षा, योग चिकित्सा, समग्र स्वास्थ्य और योग के अन्तरराष्ट्रीय प्रसार में दीर्घकालीन योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

Newspaper of 19 August, 2026

- **राज्य में ई-मित्र वाट्सऐप पर 103 सरकारी सेवाएँ उपलब्ध–**

हाल ही में राज्य सरकार ने ई-मित्र वाट्सऐप सेवा का दायरा 51 से बढ़ाकर 103 सेवाओं तक कर दिया है। 1 जुलाई, 2026 को लॉन्च की गई इस सेवा पर उपलब्ध सरकारी सेवाओं में अब तक 2.32 लाख से अधिक ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। आम नागरिक वॉट्सऐप नंबर 9461092705 के माध्यम से इन सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। वर्तमान में उपलब्ध 103 सेवाओं में 32 एप्लीकेशन, 36 डाउनलोड, 6 पेमेंट तथा 29 स्टेप्स चेक सेवाएँ शामिल हैं। इन सेवाओं को आने वाले समय में ई-मित्र मोबाइल एप्लीकेशन एवं ई-मित्र कियोस्क पर भी एपीआइ इंटीग्रेशन के माध्यम से जल्द उपलब्ध कराया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि ई-मित्र वॉट्सऐप पर राजस्व गृह, जन आधार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, डिस्कॉम, स्थानीय निकाय, शिक्षा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, पुलिस सहित विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

इन सेवाओं को मुख्य रूप से एप्लीकेशन, डाउनलोड, पेमेंट और 'स्टेटस चेक' श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

डाउनलोड–इसके तहत नागरिक जन आधार कार्ड, बोनाफाइड प्रमाण-पत्र, जमाबंदी, राशन कार्ड प्रमाण-पत्र, एनएफएसए प्रमाण-पत्र, बिजली बिल सहित विभिन्न दस्तावेज सीधे अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं।

पेमेंट–इसमें बिजली बिल भुगतान, पानी के बिल का भुगतान, बिजली विभाग की डिमांड का भुगतान तथा राजस्थान महिला निधि की 'ईएमआई पेमेंट' जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

स्टेटस चेक–इसके तहत नागरिक ई-मित्र ट्रांजैक्शन स्टेटस, जॉब कार्ड स्टेटस, बिजली शिकायत की स्थिति तथा विभिन्न योजनाओं से संबंधित आवेदन एवं लाभ की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ई-मित्र मोबाइल ऐप एवं कियोस्क पर भी उपलब्ध होंगी सेवाएँ–इन सेवाओं को ई-मित्र मोबाइल एप्लीकेशन एवं ई-मित्र कियोस्क पर भी एपीआई इंटीग्रेशन के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इस दिशा में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग तथा संबंधित विभागों द्वारा संयुक्त रूप से कार्य किया जा रहा है। इसका उद्देश्य नागरिकों को विभिन्न माध्यमों पर एक समान, सुगम एवं सुविधाजनक सेवा अनुभव उपलब्ध कराना है।

Newspaper of 20 August, 2026

- **अक्षय ऊर्जा में राजस्थान 44,135 मेगावाट सौर क्षमता के साथ पहले स्थान पर–**

हाल ही में राजस्थान ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान रचा है। राज्य की कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 50 हजार मेगावाट से अधिक पहुँच गई है। 44,135 मेगावाट क्षमता के साथ राजस्थान अक्षय ऊर्जा के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटक और सौर ऊर्जा में देश में प्रथम स्थान पर है और भारत की स्थापित सौर क्षमता में लगभग 27% का योगदान दे रहा है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने राज्य में एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति-2024 लागू की है।

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

- **राजस्थान मे शहरी निकाय चुनावों की घोषणा हुई; सभी नगरीय निकायों के चुनाव एक साथ होंगे–**

19 अगस्त, 2026 को राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के 309 शहरी निकायों के लिए चुनावों की घोषणा की। चुनाव दो चरणों में 9 सितम्बर (प्रथम चरण) व 11 सितम्बर (द्वितीय चरण) को होंगे। 14 सितम्बर को रिजल्ट घोषित किए जाऐंगे। राजस्थान के इतिहास में पहली बार सभी नगरीय निकायों में एक साथ चुनाव करवाये जा रहे हैं।

राज्य में 309 शहरी निकायों के अन्तर्गत 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद् और 248 नगर पालिकाओं को मिलाकर 10245 पार्षद पदों पर चुनाव होंगे।

राज्य में इन निकायों में कुल वोटर 1,44,03,853 हैं। सबसे ज्यादा वोटर जयपुर (2420839) में तथा सबसे कम वोटर इंद्रगढ़ (4744) है। निकाय अध्यक्ष के लिए चुनाव 21 सितंबर को होगा व परिणाम भी उसी दिन आएगा। उपाध्यक्ष 22 सितंबर को निर्वाचित किया जाएगा।

Newspaper of 21 August, 2026

- **हाल ही में केन्द्र सरकार ने मुख्य सचिव वी श्रीनिवास का कार्यकाल 6 माह बढ़ा दिया है। अब उनका कार्यकाल 28 फरवरी, 2027 तक रहेगा। केन्द्रीय कार्मिक मंत्रालय ने इसके बारे में राज्य सरकार को सूचना भेजी है।**

उल्लेखनीय है कि राजस्थान कैडर के 1989 बैच के आइएएस अधिकारी वी श्रीनिवास का कार्यकाल अगस्त, 2026 में खत्म होने जा रहा था जिसे 28 फरवरी, 2027 तक बढ़ाया गया है।

- **राजस्थान के कोटा मंडल में देश की पहली वन्दे भारत पार्सल फ्रेट ईएनयू का तकनीकी परीक्षण किया गया; 145 किमी./घंटे की रफ्तार से चली–**

अगस्त, 2026 में पश्चिम रेलवे के कोटा मंडल में देश की पहली वंदे भारत प्लेटफॉर्म आधारित सुपरफास्ट पार्सल फ्रेट ईएमयू रैक का तकनीकी परीक्षण किया जा रहा है। इस रेक का खाली अवस्था में ऑसिलेशन (वाइब्रेशन) ट्रायल सफल रहा है। परीक्षण के दौरान चौमहला से शामगढ़-गुढ़ला खंड पर हुए परीक्षण के दौरान रैक ने अधिकतम 145 किमी प्रति घंटे की गति हासिल की। इस फ्रेट ईएमयू रैक का ऑसिलेशन ट्रायल नागदा-कोटा-सवाईमाधोपुर खंड की अप और डाउन लाइनों पर किया गया। उल्लेखनीय है कि इस 16 कोच वाली फ्रेट ईएमयू को तेज गति से पार्सल और लॉजिस्टिक्स परिवहन के लिए विकसित किया गया है।

- **राज्य में यूरिया-डीएपी की लाइन खत्म होगी, घर बैठे बुक होगी खाद–**

राजस्थान में किसानों को यूरिया-डीएपी के लिए दुकानों और खाद्य केन्द्रों के चक्कर लगाने और कतारों में खड़े होने से राहत मिलेगी। किसान घर बैठे जरूरत के मुताबिक खाद बुक कर सकेगा और नजदीकी अधिकृत विक्रेता से ले सकेगा। शुरुआत में 15 जिलों में फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल लागू करेगी, बाद में इसे पूरे प्रदेश में विस्तार दिया जाएगा।

नई व्यवस्था से खाद की मांग, बुकिंग, आवंटन, उपलब्धता और वितरण डिजिटल निगरानी में होगा। किसानों की जरूरत के आधार पर ही आपूर्ति की जाएगी।

इस योजनान्तर्गत जिलेवार मांग लगातार ट्रेक होगी। किसी क्षेत्र में मांग बढ़ने पर अतिरिक्त आपूर्ति की जाएगी। इससे जरूरत वाले क्षेत्र तक खाद पहुँचाना आसान होगा। इसके तहत ऑनलाइन बुकिंग के बाद किसान को 48 घंटे के लिए वैध टोकन मिलेगा। इस अवधि में विक्रेता से खाद लेनी होगी। समय सीमा निकलने पर टोकन समाप्त होगा और दोबारा बुकिंग करनी पड़ेगी।

- **राजस्थान में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 9 व 11 में नई परीक्षा व प्रमोशन प्रक्रिया लागू की; कक्षा नौ में अब तीन भाषाएँ अनिवार्य रहेंगी, गणित व विज्ञान में एडवांस स्तर चुनने का विकल्प मिलेगा–**

राजस्थान में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 9वीं व 11वीं की परीक्षा प्रक्रिया और प्रमोशन नीति में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। संशोधित व्यवस्था के तहत कक्षा नौ में तीन भाषाओं की पढ़ाई अनिवार्य की जा रही है। इनमें तीसरी भाषा को केवल स्कूल स्तर पर आकलित किया जाएगा और इसे पास करना जरूरी होगा। वहीं गणित और विज्ञान में एडवांस स्तर चुनने का विकल्प मिलेगा। व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाया गया है, जबकि कम्प्यूटेशनल थिंकिंग एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉड्यूल इस सत्र से स्कूल आधारित आकलन के साथ शुरू होंगे और 2027-28 से ये अनिवार्य विषय होंगे। कक्षा नौ के विद्यार्थियों के लिए तीसरी भाषा आर-3 अनिवार्य योग्यता विषय होगी। यदि विद्यार्थी कक्षा नौ में आर-3 में क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो अन्य प्रमोशन शर्तें पूरी होने पर उसे कक्षा दस में प्रवेश मिलेगा, लेकिन कक्षा दस में रहते हुए उसे कक्षा नौ की तीसरी भाषा की परीक्षण पास करनी होगी। यानी कक्षा दसवीं की बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए आर-3 में क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा।

गणित-विज्ञान में 80 अंक का सामान्य पेपर, एडवांस के लिए 25 अंक अतिरिक्त–एडिशनल डायरेक्टर ऑफ

एजुकेशन के अनुसार गणित और विज्ञान में दो स्तर की व्यवस्था लागू की गई है। सभी विद्यार्थियों के लिए सामान्य पाठ्यक्रम के आधार पर 80 अंकों की तीन घंटे की परीक्षा होगी। जो विद्यार्थी एडवांस स्तर लेना चाहते हैं, उन्हें गणित एडवांस और विज्ञान एडवांस की एक-एक अतिरिक्त परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा 25 अंकों की ओर एक घंटे की होगी तथा इसमें उच्च स्तरीय सोच पर आधारित प्रश्न होंगे। एडवांस के अंक प्रमोशन या कुल योग में नहीं जुड़ेंगे।

छह विषय ही प्रमोशन का मुख्य आधार–कक्षा नौ में भाषा-1, भाषा-2, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और व्यावसायिक शिक्षा छह मुख्य विषय होंगे। इन्हीं के आधार पर प्रमोशन तय होगा। विद्यार्थी को प्रत्येक मुख्य विषय में आंतरिक या प्रायोगिक और बाह्य आकलन में अलग-अलग 33% अंक लाने होंगे। वार्षिक परीक्षा में भी प्रत्येक मुख्य विषय में कम से कम 25% अंक जरूरी होंगे। कक्षा नौ में व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य किया है। इंडिविजुअल इन सोसाइटी, कला शिक्षा तथा शारीरिक शिक्षा एवं वेल-बीइंग भी अनिवार्य पाठ्यक्रम में शामिल हैं।

3 विषयों तक कंपार्टमेंट का मौका–छह मुख्य विषयों में अधिकतम तीन विषयों में असफल विद्यार्थी कंपार्टमेंट परीक्षा दे सकेगा। यह परीक्षा अप्रैल के दूसरे या तीसरे सप्ताह में होगी। कंपार्टमेंट में भी संबंधित विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक और आंतरिक आकलन या प्रायोगिक में 33 प्रतिशत अंक जरूरी होंगे। कंपार्टमेंट परीक्षा में ग्रेस मार्क्स का लाभ नहीं मिलेगा।

■ केन्द्र की योजनाओं के बजट के लिए नई एसओपी, बार-बार वित्तीय मंजूरी का झंझट खत्म हुआ–

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) के वित्तीय प्रबंधन को अधिक पारदर्शी, सुगम और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार ने नई एसओपी जारी की है। एसएनए-स्पर्श (SNA-SPARSH) मॉडल के तहत मदर सेक्शन जारी करने और उनके उपयोग को लेकर वित्त विभाग ने सभी संबंधित विभागों को दिशा-निर्देश जारी किए है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि मदर सेक्शन जारी होने के बाद योजनाओं के लिए बार-बार वित्त विभाग से वित्तीय स्वीकृति लेने की प्रक्रिया समाप्त हो सकेगी।

नई व्यवस्था में जिन केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत एक से अधिक राज्य संबद्ध योजनाएँ (SLS) संचालित हैं, उनके लिए संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों से समन्वय कर प्रत्येक SLS के लिए अलग-अलग मदर सेंक्शन जारी कराए जाएंगे। इससे प्रत्येक योजना में बजट आवंटन और खर्च की सटीक निगरानी हो सकेगी। साथ ही एक योजना की राशि को दूसरी योजना में उपयोग किए जाने की आशंका भी कम होगी।

अब वित्त विभाग में फाइल भेजने की जरूरत नहीं–सेक्शन जारी होने के बाद अब प्रशासनिक विभागों और विभागध्यक्षों को इसके आधार पर बार-बार वित्तीय स्वीकृति लेने के लिए वित्त (व्यय) विभाग को ऑनलाइन या ऑफलाइन फाइल भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। मदर सेक्शन अथवा व्यय की मैपिंग की प्रक्रिया निर्धारित व्यवस्था के अनुसार संबंधित विभागों के स्तर पर ही पूरी की जाएगी।

■ राजस्थान विधानसभा में राजस्थान वन संरक्षण अधिनियम 2026 रखा गया; इस अधिनियम के तहत राज्य में 4 फीट 6 इंच से ऊँचे पेड़ काटने पर सजा का प्रावधान–

20 अगस्त, 2026 को राजस्थान विधानसभा में 'द राजस्थान ट्रीज (प्रोटेक्शन) बिल-2026' यानी राजस्थान वन संरक्षण अधिनियम 2026 रखा गया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने राजस्थान वृक्ष संरक्षण विधेयक 2026 को पुर्नस्थापित करने की अनुमति मांगी। इस बिल में 4 फीट 6 इंच या इससे बड़े निजी जमीन से लेकर सरकार या संस्थागत जमीन, कामर्शियल जमीन पर खड़े पेड़ को काटने पर प्रतिबंध से संबंधित है। इसमें राजस्थान की किसी जमीन पर लगे 29 प्रकार के पेड़ों को काटना प्रतिबंधित किया गया है। बिल में 29 प्रजातियों के पेड़ों को संरक्षित-प्रतिबंधित श्रेणी में रखने का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित मसौदे के अनुसार, गैर-वन भूमि पर भी बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के इन पेड़ों को काटने पर 1 लाख रुपये तक जुर्माना और 1 वर्ष तक का सश्रम कारावास हो सकता है। पश्चिमी राजस्थान में खेजड़ी काटने के खिलाफ संतों, समाजों के लंबे आंदोलन के बाद सरकार पहली बार यह कानून लाई है।

इन 29 पेड़ों को काटने पर होगी कार्रवाई–खेजड़ी, रोहिड़ा, जाल (खारा और मीठा), पीपल, बड़, शिवनख बरगद, वट वृक्ष, मोखा, कडायो, पाडल, गूंदा, काली शीशम, नीम, महुआ, सागौन, साल चिरौंजी, सिल्ला, गूलर, पाकड़, पलाश (ढाक), बेल, इमली, जामुन, खिरनी, कैथाल, सोड़ा, तेंदू, कैर, बीजा साल, असना, कुसुम, रीठा, सलई, हल्दू, बाकली, धोक, खैर आदि को संरक्षित पेड़ों की श्रेणी में शामिल किया है।

संरक्षित जमीनों के अलावा इन जमीनों पर पेड़ काटने पर रोक–संरक्षित भूमियों के अलावा कृषि, गैर कृषि, ग्रामीण, नगरीय क्षेत्र की निजी भूमि, सरकारी भूमि, निकायों को आंतरित की गई भूमि, भवनों, संस्थानिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय परिसर की भूमि, भवनों, संस्थानिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय परिसर की भूमि, सड़क, तट, नहर, नदी किनारे की भूमि पर पेड़ काटना प्रतिबंधित किया गया है।

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

Newspaper of 22 August, 2026

■ **राजस्थान सहित 7 प्रदेशों में कलक्टर कर सकेंगे नागरिकता पर फैसला; केन्द्र सरकार ने दिया अधिकार, जल्द खत्म होंगे लंबित मामले–**

नागरिकता पाने की प्रक्रिया को आसान और तेज करने के लिए केन्द्र सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। नागरिकता (तीसरा संशोधन) नियम, 2026 के तहत अब गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के संबंधित जिला कलक्टर सीएए की धारा 6बी के तहत पात्र आवेदनों पर सीधे फैसला कर सकेंगे। असम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र इसके दायरे से बाहर है। नई व्यवस्था में कलक्टर आवेदन प्राप्त करने, दस्तावेजों की जाँच, जरूरी पूछताछ और पात्रता तय करने के बाद नागरिकता देने की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। वे आवेदक को निष्ठा की शपथ भी दिला सकेंगे। यानी अब सीएए के तहत पात्र आवेदन के अंतिम निस्तारण के लिए केन्द्र की सशक्त समिति के स्तर तक जाने की जरूरत नहीं होगी। समितियों के पास पहले से लंबित आवेदन भी संबंधित कलक्टरों को ट्रांसफर किए जाएंगे। सरकार के सीएए के तहत किए गए नए प्रावधानों से लंबित नागरिकता आवेदनों के जल्द निपटारे की उम्मीद है। अकेले राजस्थान में करीब 600 आवेदन लंबित हैं।

■ **राजस्थान से डॉ. दिव्येंदु सेन व डॉ. वर्तिका राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित–**

शिक्षक दिवस (5 सितंबर, 2026) पर 5 सितंबर को दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान के लिए राजस्थान के दो शिक्षकों का चयन किया गया है। दोनों को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी।

- **डॉ. दिव्येंदु सेन**–महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, पचपहाड़ झालावाड़ के शिक्षक दिव्येंदु सेन का चयन ग्रामीण विद्यार्थियों को कम्प्यूटर व विभिन्न सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षित करने के लिए दिया गया है।
- **डॉ. वर्तिका गुलाटी**–राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, टूमली का बास, चाकसू (जयपुर) की शिक्षिका डॉ. वर्तिका गुलाटी का पुरस्कार के लिए चयन नवाचार, तकनीक एवं गतिविधि आधारित शिक्षण को विशेष स्थान देने पर किया गया है।

गौरतलब है कि देशभर से 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन हुआ है।

■ **जयपुर डेयरी (सरस डेयरी) में दूध की प्रोसेसिंग क्षमता 12 लाख से 20 लाख लीटर हुई–**

हाल ही में जयपुर डेयरी ने 150 करोड़ रुपए की लागत से नया दूध प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किया है। साथ ही डेयरी की दूध प्रोसेसिंग क्षमता 12 लाख से बढ़कर 20 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई है यानी अब रोजाना 8 लाख लीटर अतिरिक्त दूध प्रोसेस किया जा सकेगा। वहीं, दूध की पैकिंग क्षमता भी 10 लाख से बढ़कर 16.50 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई है। इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा। मांग बढ़ने पर दूध के साथ पनीर, घी, मक्खन और अन्य सरस उत्पादों का उत्पादन भी बढ़ाया जा सकेगा। आधुनिक मशीनरी, नए बॉयलर और तकनीकी सुविधाओं के जरिए प्लांट की कार्यक्षमता बढ़ाई गई है। इसका उद्देश्य क्षमता बढ़ने से दूध की उपलब्धता के साथ उसके अलग-अलग उत्पादों से प्रसंस्करण की क्षमता भी बढ़ेगी।

जयपुर डेयरी के नए प्लांट में रोजाना 70 मीट्रिक टन तक घी का उत्पादन किया जा सकेगा। दूध की प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ने से पनीर, मक्खन, और अन्य उत्पादों का उत्पाद भी मांग के अनुसार बढ़ाया जा सकेगा।

■ **राज्य सरकार ने पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को राज्य में लागू किया–**

किसानों को मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों से होने वाले आर्थिक नुकसान से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को खरीफ 2026 से रबी 2026-27 तक दो फसल मौसमों के लिए प्रदेश में लागू किया है। योजना के तहत प्रतिकूल मौसम एवं अवांछित मौसमी घटनाओं से फसल को होने वाले नुकसान के विरुद्ध किसानों को बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार द्वारा खरीफ 2026 की वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के बीमा के लिए 11 अगस्त, 2026 को योजना की अधिसूचना जारी की गई है। योजना के क्रियान्वयन के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है।

41 जिलों में अधिसूचित होंगी फसलें–प्रदेश के सभी 41 जिलों में खरीफ 2026 एवं रबी 2026-27 के लिए विभिन्न वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों को अधिसूचित किया गया है।

- खरीफ 2026 में हरी मिर्च, भिंडी, प्याज, टमाटर, अरंडी, अनार, टिंडा, मेहंदी, संतरा एवं किन्नू को शामिल किया गया है।
- रबी 2026-27 में आंवला, बैंगन, सौंफ, फूलगोभी, लहसुन, प्याज, मटर, टमाटर, आलू, अमरूद, नींबू, आम, खरबूजा, तरबूज, बेर, पत्तागोभी, मौसमी एवं पपीता जैसी फसलों को योजना में शामिल किया गया है।

ऋणी, गैर-ऋणी एवं पात्र बंटाईदार किसानों को लाभ–योजना के तहत ऋणी, गैर-ऋणी एवं पात्र बटाईदार किसान

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करवा सकेंगे। फसल बीमा करवाना पूर्णतः स्वैच्छिक है।

- ऋणी एवं गैर-ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा करवाने हेतु एग्रीस्टैक आईडी अनिवार्य होगी।
- ऋणी किसान यदि योजना से बाहर रहना चाहते हैं तो निर्धारित समय सीमा में संबंधित वित्तीय संस्था को ऑप्ट-आउट घोषणा-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।
- **किसान को अधिकतम 5% प्रीमियम देना होगा–** पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए किसान द्वारा बीमित राशि का अधिकतम 5 प्रतिशत प्रीमियम वहन किया जाएगा। निर्धारित सीमा से अधिक प्रीमियम राशि का वहन केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
- किसान योजना का लाभ लेने के लिए अपने निकटतम बैंक शाखा, सहकारी संस्था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सीएससी, डाकघर अथवा अधिकृत बीमा माध्यम से फसल बीमा करवा सकते हैं।
- मौसम आधारित फसल बीमा योजना किसानों की आय को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ उन्हें आधुनिक एवं उन्नत कृषि गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करती है।
- फसल जोखिम के विरुद्ध बीमा सुरक्षा मिलने से कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह को भी मजबूती मिलती है।

■ राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में राजस्थान ने 5 पदक जीते–

16-21 अगस्त, 2026 को 5वीं इंडिया ताइक्वांडो क्योरुगी नेशनल चैंपियनशिप 2026-27 का आयोजन पुणे, महाराष्ट्र में हुआ। कैडेट, जूनियर एवं सीनियर वर्गों में राजस्थान ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 5 पदक जीते।

- तन्विष्ठा जोधा (जयपुर) ने जूनियर महिला अंडर-42 किग्रा तथा काजल शेखावत-कैडेट महिला अंडर-44 किग्रा में स्वर्ण पदक जीता।
- भुवनेश ने कैडेट पुरुष अंडर-57 किग्रा तथा प्रतिज्ञा-कैडेट महिला अंडर-55 किग्रा में रजत पदक जीता।
- रिया तंवर ने सीनियर महिला ओवर-73 किग्रा में कांस्य पदक जीता।

■ पूनम कंवर (RPSF जवान) ने माउंट एल्ब्रुस पर फहराया तिरंगा–

21 अगस्त, 2026 को सीकर जिले के झाड़ली गाँव की पर्वतारोही एवं रेलवे सुरक्षा विशेष बल (RPSF) की जवान पूनम कंवर ने रूस स्थित यूरोप की सबसे ऊँची चोटी माउंट एल्ब्रुस (5642 मीटर/18510 फीट) फतह कर तिरंगा फहराया। वे इससे पहले माउंट किलीमंजारो (अफ्रीका)-2024 और माउंट कोज़ियस्को (ऑस्ट्रेलिया)-2025 फतह कर चुकी हैं।

Newspaper of 23 August, 2026

■ सौर ऊर्जा के लिए पायलट प्रोजेक्ट; जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम के 172 जीएसएस पर मेगा बैटरी बैंक लगेंगे–

हाल ही में विद्युत वितरण निगम ने पीपीपी मॉडल के तहत सौर ऊर्जा से बनी बिजली को स्टोर कर आवश्यकतानुसार सप्लाई सुचारू रखने के लिए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसके तहत शहरी क्षेत्रों के ग्रिड सब स्टेशनों (जीएसएस) पर भारी क्षमता के बैटरी बैकअप सिस्टम लगाए जाएंगे। पहले चरण में तीना डिस्कॉम से 172 जीएसएस का चयन किया गया है। इनमें जयपुर के 12, अजमेर के 10 और जोधपुर डिस्कॉम के सर्वाधिक 150 जीएसएस शामिल है। यहाँ जल्द ही ट्रांसफार्मर एरिया में बैटरी बैकअप पैनल बोर्ड तैयार कर ट्रायल शुरू किया जाएगा।

दिन में सोलर में बनने वाली बिजली को जीएसएस के बैटरी बैंक में स्टोर किया जाएगा। शाम और रात में पीक डिमांड के दौरान सप्लाई होगी। पहले चरण में जोधपुर, सीकर, झुंझुनूँ, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर और उदयपुर के शहरी जीएसएस को प्राथमिकता दी है।

प्रोजेक्ट के लिए तय किए गए 3 प्रमुख मापदंड–

1. **स्थान की उपलब्धता–**बैटरी बैंक और कंट्रोल यूनिट स्थापित करने के लिए जीएसएस ट्रांसफार्मर के पास न्यूनतम 15 वर्ग मीटर खाली व सुरक्षित भूमि होनी चाहिए।
2. **लंबी अवधि का अनुबंध–**संबंधित फर्म के साथ 10 वर्ष का एमओयू किया जाएगा।
3. **तकनीकी प्राथमिकता–**ट्रायल के लिए केवल उन्हीं जीएसएस का चुनाव किया जा रहा है, जहाँ रूफटॉप और कमर्शियल सोलर प्लांट का कंसंट्रेशन सबसे अधिक है।

Newspaper of 26 August, 2026

■ यतीन्द्र एस. यादव का 'राजभाषा गौरव पुरस्कार' के लिए चयन हुआ–

25 अगस्त, 2026 को वर्ष 2025 के राजभाषा गौरव पुरस्कारों के परिणाम घोषित किए। इसमें यतीन्द्र एस. यादव की हिंदी पुस्तक 'एनीमेशन की दुनिया' को ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन श्रेणी के प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए चुना गया है।

- उनका चयन इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर विज्ञान एवं अन्य ज्ञान-विज्ञान विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन वाली राजभाषा गौरव श्रेणी में प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए हुआ है।

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

- इस श्रेणी के प्रत्येक प्रोत्साहन पुरस्कार के अंतर्गत ₹40000 प्रमाण-पत्र और स्मृति-चिह्न प्रदान किए जाते हैं।

Newspaper of 29 August, 2026

अब टूटी सड़कें 72 घंटे में ही रिपेयर हो सकेंगी, जीपीएस से होगा वेरिफिकेशन; 'सुगम पथ पोर्टल' पर दर्ज होगा सड़क से जुड़ा पूरा डिजिटल रिकॉर्ड–

मानसून में बारिश के साथ सड़कों पर उभरने वाले गड्ढों से निपटने के लिए सरकार ने सड़क पर गड्ढे खोजने और फिर जीपीएस से उनकी मरम्मत का हिसाब रखने का सिस्टम तैयार किया है। नियमित सर्वे-गश्त के जरिए सड़कों पर गड्ढे चिह्नित किए जा रहे हैं। इसके बाद 48 से 72 घंटे के भीतर कोल्ड मिक्स या हॉट मिक्स से पैच रिपेयर कराने का टारगेट है। अब सड़क पर गड्ढा मिलने से लेकर उसके भरने तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल निगरानी में रहेगी। मरम्मत के बाद जीपीएस फोटो और डिजिटल रिकॉर्ड के जरिए यह भी वेरिफाई किया जाएगा कि जहाँ गड्ढा मिला था, वहीं वास्तव में रिपेयर हुआ या नहीं। 'सुगम पथ पोर्टल' के जरिए काम की प्रगति पर नजर रखी जा रही है। अभियान की सबसे खास बात इसका डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम है। पैच रिपेयर के बाद GPS फोटो और डिजिटल रिकॉर्ड के जरिए काम का सत्यापन किया जा रहा है। इससे संबंधित सड़क का स्थान, चिह्नित गड्ढा, मरम्मत की स्थिति और कार्य की प्रगति रिकॉर्ड में रहेगी।

राजस्थान प्रदेश की 48 कोर्ट होंगी पेपरलेस; एलईडी पर दस्तावेज और रिकॉर्ड दिखेगा; न्यायान सॉफ्टवेयर से तारीख, पेशी जैसे काम होंगे–

अदालतों में अब फाइलों के ढेर और कागजों पर चलने वाली सुनवाई का दौर खत्म होगा। प्रदेश की 48 अदालतों को पेपरलेस किया जा रहा है। इनमें 36 एनआई एक्ट और 12 कॉमर्शियल कोर्ट हैं। नई व्यवस्था में केस की पेशी से लेकर दस्तावेज पेश करने, सुनवाई और ऑर्डरशीट तैयार करने तक की प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी।

15 सितम्बर के बाद पेपरलेस काम शुरू किया जाएगा। पेपरलेस कोर्ट के बाहर एलईडी लगाई जाएगी। इस पर वादी-प्रतिवादियों को सुनवाई के लिए केस की तारीख दिखाई जाएगी। साथ ही, कोर्ट रूम में जज की कुर्सी के पीछे एलईडी स्क्रीन में वादी-परिवादी केस से संबंधित दस्तावेज और रिकॉर्ड देख सकेंगे। इसके लिए 'न्यायान' सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। अदालतों में अगली तारीख पेशी और ऑर्डरशीट जैसे काम हो सकेंगे।

वकीलों के लिए दो कम्प्यूटर, वहीं से पेश होंगे दस्तावेज– अधिवक्ताओं के लिए दो कम्प्यूटर लगाए गए हैं। दोनों पक्ष दस्तावेज ऑनलाइन पेश करेंगे। सुनवाई के लिए स्पीकर और माइक भी लगाए गए हैं। यानी कागजी फाइल लेकर कोर्ट रूप में दस्तावेज पेश करने की जगह डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर सुनवाई होगी।

Newspaper of 31 August, 2026

ब्रजेन्द्र कुमार सिंहल को प्रथम 'मीरां मेड़तणी साहित्य पुरस्कार' मिला–

जयपुर के साहित्यकार एवं शोधकर्त्ता डॉ. ब्रजेन्द्र कुमार सिंहल को उनकी पुस्तक 'मीरांबाई : प्रामाणिक जीवनी एवं मूल पदावली' के लिए प्रथम 'मीरां मेड़तणी साहित्य पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। उनकी उक्त पुस्तक मीरांबाई के जीवन एवं पदावली पर शोधपरक कृति है।

वर्ष 2026 की पहली छमाही में राजस्थान में 10.92 करोड़ पर्यटक यात्राएँ दर्ज हुई–

राजस्थान पर्यटन विभाग के अनुसार जनवरी-जून 2026 के दौरान प्रदेश में कुल 10,92,04,101 (10.92 करोड़) पर्यटक यात्राएँ दर्ज की गईं। इनमें 10.83 करोड़ घरेलू (99.2%) तथा 8.44 लाख विदेशी (0.8%) पर्यटक यात्राएँ शामिल हैं।

- सीकर सर्वाधिक 1.56 करोड़ घरेलू पर्यटक यात्राओं के साथ पहले स्थान पर रहा। इसके बाद चित्तौड़गढ़-1.34 करोड़ और जैसलमेर-1.18 करोड़ रहे।
- जयपुर में सर्वाधिक 2,56,293 विदेशी पर्यटक यात्राएँ दर्ज हुईं, जो राज्य की कुल विदेशी यात्राओं का लगभग 30% है।

33वें मथुरादास माथुर क्रिकेट अवॉर्ड्स-2026 घोषित हुए–

राजस्थान क्रिकेट में 2025-26 के प्रदर्शन के आधार पर 33वें मथुरादास माथुर अवॉर्ड के लिए अशोक शर्मा, कुशाग्र ओझा और शिफान खान का चयन किया गया। पुरस्कार समारोह 6 सितम्बर, 2026 को मथुरादास माथुर की जयंती पर आयोजित हुआ।

- सीनियर वर्ग में जयपुर के तेज गेंदबाज अशोक शर्मा चुने गए। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 22, विजय हजारे ट्रॉफी में 13 और रणजी ट्रॉफी में 14 विकेट लिए।
- जूनियर वर्ग में भीलवाड़ा के कुशाग्र ओझा तथा सब-जूनियर वर्ग में जयपुर के बल्लेबाज शिफान खान को चुना गया। शिफान ने विजय मर्चेंट ट्रॉफी में 241 रन बनाए।
- सीनियर विजेता को ₹15000 व जूनियर विजेताओं को ₹7500 तथा प्रमाण पत्र व स्मृति चिह्न दिए जाएंगे।

□□□

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

संजीव®

51 वर्षों से आपका विश्वसनीय

आपकी सफलता में सदैव आपका सहयोगी

CET 10+2 के लिए विशेष उपयोगी पुस्तकें

New Edition

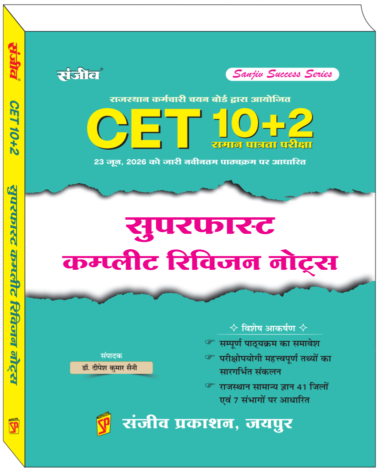

MRP ₹400
(288 पेज में सम्पूर्ण पाठ्यक्रम)

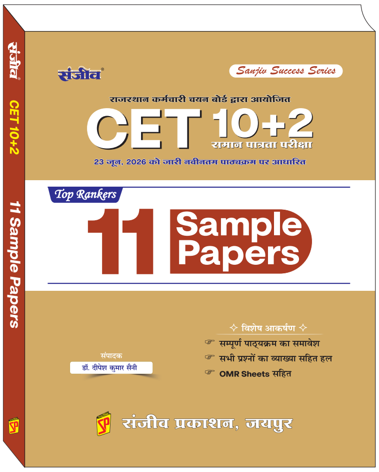

MRP ₹300
(पुस्तक में 11 Blank OMR Sheet)

MRP ₹400
(सम्पूर्ण रंगीन मानचित्रावली)

संजीव प्रकाशन द्वारा प्रकाशित अन्य प्रमुख पुस्तकें

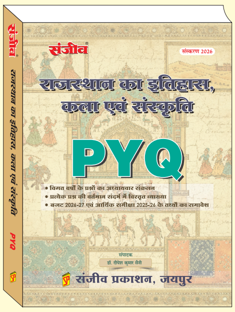

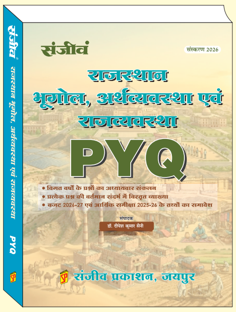

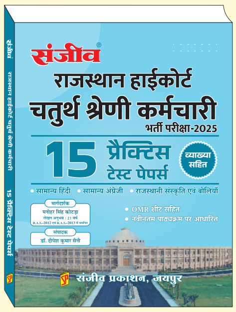

संजीव प्रकाशन

Join Our App

संजीव Telegram चैनल, App एवं Website से परीक्षा उपयोगी पाठ्य सामग्री नि:शुल्क प्राप्त करें। साथ ही संजीव App एवं वेबसाइट से आप Books एवं E-Books भी खरीद सकते हैं।

प्रकाशक–संजीव प्रकाशन, जयपुर

Visit us at : www.sanjivprakashan.com

संजीव प्रकाशन

Join Our Telegram